प्रत्येक सोमवार को हल्द्वानी से प्रकाशित

RNI No.- UTTHIN/2017/73662

कुमाऊं जनसन्देश

www.kumaonjansandesh.com

वर्ष – 7 | अंक – 5 | हल्द्वानी(नैनीताल) | सोमवार 30 दिसम्बर 2024 | पृष्ठ – 4 | मूल्य – 1

अल्मोड़ा में गुलाबी ई-रिक्शा चलाती नजर आएंगी महिलाएं

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि) परियोजना बनेगी सहारा

अल्मोड़ा। शहर की सड़कों पर जल्द ही महिलाएं ई-रिक्शा चलाती नजर आएंगी। शुरूआत में स्वयं सहायता समूह की 18 महिलाओं ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि) परियोजना द्धग्रामोत्थान योजनाऋ को ई-रिक्शा उपलब्ध करा दिये गए हैं। स्वरोजगारी महिलाओं की अलग पहचान के मददेनजर ई-रिक्शा का गुलाबी रंग तय किया गया है। डीएम और सीडीओ ने भी ट्रायल के दौरान ई-रिक्शा में बैठकर महिलाओं को प्रेरित

किया। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि) परियोजना द्धग्रामोत्थान योजनाऋ के द्वारा स्वयं सहायता समूहों की 18 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इस योजना के तहत 10 ई रिक्शा वाहन समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराई गई हैं।

इन ई रिक्शा वाहनों का ट्रायल आरसीएम मॉल अल्मोड़ा से शिखर होटल तक किया गया। ट्रायल कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रयास महिलाओं की आर्थिकी को बढ़ावा देने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बल देगा। उन्होंने कहा कि आज यहां इसका ट्रायल किया गया है, इसका विधिवत शुभारंभ भी जल्द ही किया जाएगा। समूहों की इन महिलाओं का प्रशिक्षण भी पूर्व में कराया गया है जिससे वे इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। ट्रायल के दौरान छोलिया दलों को भी रवाना किया गया जिससे अल्मोड़ा एवं कुमाऊं की सांस्—तिक पहचान को भी बढ़ावा दिया जा सके। जिलाधिकारी एवं सीडीओ ने ई रिक्शा में बैठकर सफर भी तय किया। इस दौरान सीडीओ दिवेश शाशनी, अपर जिलाधिकारी सीएम मार्तोलिया, परिवहन अधिकारी अखिलेश चौहान, मैनेजर रिप संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।

नए साल में 123250 नए मतदाता होंगे वोटर लिस्ट में शामिल

देहरादून। उत्तराखण्ड में आगामी जनवरी माह में एक लाख 23 हजार से अधिक नए मतदाता शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं।

प्रदेश में इस वर्ष 123250 नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं, जिसका अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। नई वोटर लिस्ट में कुल 123250 मतदाताओं में से 58917 पुरुष, 64322 महिला एवं 11 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर अभियान यु) स्तर पर चलाया जाए। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदवार सुपर चेकिंग के लिए भी विभिन्न जनपदों का दौरा करने के लिए निर्देशित किया गया था।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवर्ष विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तरगत वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया संचालित की जाती है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने हेतु साल भर में 4 अर्हता तिथियां नियत की गई हैं, जिसमें 1 जनवरी,1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक फश्चर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देशों के क्रम में सभी अधिकारियों को अलग-अलग जनपदों में सुपर चेकिंग अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुपर चेकिंग अभियान में नियमित रुप से अधिकारियों द्वारा स्वयं पोलिंग बूथ पर सुपर चेकिंग करते हुए मतदाताओं से फीडबैक लिया गाय। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत प्रदेश में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। बीते 5 सालों में प्रदेश में 1 जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर 1135590 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए हैं। जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 533007 ,महिला मतदाताओं की संख्या 602418 व थर्ड जेंडर 165 शामिल रहे। 1 जनवरी के आधार पर वर्ष 2020 में 118732, वर्ष 2021 में 140528 मतदाता, वर्ष 2022 में 360686 मतदाता, वर्ष 2023 में 134461 मतदाता एवं वर्ष 2024 में 257933 मतदाता शामिल किए गए।

वाहन चालकों को प्रतिवर्ष तीन हजार रुपए वर्दी भत्ता मंजूर

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय के इतर राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालको को प्रतिवर्ष 3000 रुपए वर्दी भत्ता अनुमन्य करने का शासनादेश जारी होने पर राज्य सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन का आभार व्यक्त किया है। परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने कहा कि अब तक केवल सचिवालय के वाहन चालकों को ही वर्दी भत्ता प्रदान किया जा रहा था। किन्तु अब अधीनस्थ कार्यालयों के वाहन चालकों को भी वदह्न भत्ते का यथोचित लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा मुख्य सचिव द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अधिवर्षता की तिथि को ही उसके सेवानिवृत्तिक लाभ प्रदान करते हुए उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किये जाने समबन्धी शासनादेश जारी करने पर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की गई है।परिषद के प्रदेश प्रवक्ता ने शासन से यह अनुरोध भी किया है कि विगत कैबिनेट बैठक में 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों हेतु नोशनल वेतन वृद्धि) के निर्णय का शासनादेश एवं राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु एलटीसी प्रदान किए जाने हेतु संशोधित शासनादेश भी शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाए। परिषद के प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु 5 बैंकों के साथ किए गए कारपोरेट सैलरी पैकेज के एमओयू को सही प्रकार से लागू करते हुए कार्मिको के वेतन भुगतान सम्बन्धित खाते को कारपोरेट खाते मे परिवर्तित करने हेतु राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा निदेशक कोषागार से मुलाकात कर सम्बन्धित बैंकों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

डिग्री पाकर खिल उठे नव युवाओं के चेहरे

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने बीती शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए। डिग्रियां पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में सुमित शर्मा और ;षभ उनियाल को प्रो.गजेन्द्र सिंह ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया गया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षण उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है और उनके सपनों को साकार करने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि आज का युग परिवर्तन, नवाचार और आधुनिकीकरण का है, जहां विज्ञान

और प्रौद्योगिकी के माध्यम से 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान खोजने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे केवल नौकरी की तलाश तक सीमित न रहें, बल्कि अपने ज्ञान, रचनात्मक सोच और कठिन परिश्रम के बल पर स्टार्टअप शुरू करें और सफल उद्यमी बनें।

राज्यपाल ने युवाओं को देश की प्रगति और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास विशाल युवा शक्ति है, जो राष्ट्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उसे विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें, नवाचार को अपनाएं और उद्यमिता के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को गति दें। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग गांवों, गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए करें। उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र की बेहतरी में योगदान देने से ही उनकी शिक्षा और उपाधि की सार्थकता सि) होगी।राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दून विश्वविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (नैक) द्वारा 'ए' ग्रेड से मान्यता प्राप्त हुई है, जो इसके उच्च शैक्षणिक और शोध कार्यों का प्रमाण है। उन्होंने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के पूर्व निदेशक पद्म भूषण प्रो. पी बलराम ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने उपाधि धारकों को बधाई और भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पद्मश्री प्रीतम भरतवाण,माधुरी बड़थ्वाल, बंसती बिष्ट, प्रेमचंद शर्मा और विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, विद्या परिषद, कार्य परिषद के सदस्य और अन्य लोग उपस्थित रहे।

सम्पादकीय...

कानूनी परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहा गांèी परिवार

लाख कोशिश के बावजूद गांधी परिवार अपनी कानूनी परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहा है। 2014 के बाद से ही उसके लिए यह स्थिति पैदा हुई है। उसे अदालतों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आजादी के तत्काल बाद से ही नेहरू-गांधी परिवार कानून से ऊपर माना जाता रहा। तरह-तरह की कानूनी परेशानियों से यह परिवार साफ बच निकलता रहा, पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थिति को बदल कर रख दिया है। इसी कारण गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड मामले की गिरफ्त में है। नतीजतन गांधी परिवार में अजीब तरह की बेचौनी है। उसका असर राहुल गांधी की देह-भाषा पर है और उनकी जुबान पर भी। राहुल गांधी और उनके लोग कभी चुनाव आयोग तो कभी अदालत के खिलाफ बोलते हैं और कभी संसद के पीठासीन पदाधिकारियों को अपमानित करते हैं। इससे उन्हें कोई राजनीतिक या चुनावी लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं। राहुल गांधी यह समझते हैं कि मोदी तथा संवैधानिक संस्थाओं पर भी तरह-तरह के झूठे आरोप लगाकर उन्हें अपने स्तर पर नीचे खींच लाएंगे, ताकि आम लोग मोदी को उनसे बेहतर न मानें, पर ऐसा तो तब होगा जब प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण हाथ लगे। नेहरू-गांधी परिवार में 2014 तक यह धारणा बनी हुई थी कि यह परिवार किसी भी कानून से ऊपर है। भारत उसकी मिल्कियत है। उसे ही इस देश पर शासन करने का नैसर्गिक अधिकार है। मोदी के सोनिया-राहुल की छटपटाहट का सबसे बड़ा कारण यही है। इससे पहले इस परिवार को इतनी छूट रही कि एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहा करते थे कि ''प्रथम परिवार'' को छूना तक नहीं है। ऐसे अघोषित विशेषाधिकार प्राप्त परिवार के सामने जब कानूनी गिरफ्त से बचने का कोई तरीका नजर न आए तो उसकी मनोदशा कैसी होगी, इसकी कल्पना कर लीजिए। इस तनाव और छटपटाहट के कारण ही राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका भी गरिमापूर्ण ढंग से निभाने में विफल हैं। यदि प्रतिपक्ष का नेता विवेकपूर्ण ढंग से ठोस तथ्यों पर आधारित अपनी बातें रखे तो जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़े, छवि बेहतर हो, पर राहुल गांधी ने अपनी असंगत बोली तथा असामान्य देह भाषा के जरिए सदन की गरिमा गिराने की जितनी कोशिश की, वह अभूतपूर्व है। अपने परिवार के इतिहास के गर्व में पल रहे राहुल गांधी ने पूर्वजों के इतिहास के किस्से सुन रखे होंगे। संभवत: अपने प्रति उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद वह मौजूदा सरकार से भी कर रहे होंगे। अब यह संभव नहीं। गांधी परिवार पर पहला कानूनी संकट नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आया था।1949 में लंदन में भारतीय उच्चायुक्त वीके —ष्णमेनन पर जीप घोटाले का गंभीर आरोप लगा। कांग्रेसी नेता अनंत शयनम अयंगार की जांच कमेटी ने उन्हें सरसरी तौर पर दोषी माना और विस्तृत न्यायिक जांच की सिफारिश की। न्यायिक जांच के परिणामस्वरूप सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक जानकारियां सामने आने का खतरा दिखा। इसलिए गृह मंत्री ने 30 सितंबर 1955 को लोकसभा में यह घोषणा कर दी कि जीप घोटाले के इस मामले को बंद कर दिया गया है। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद कर दिया था तो यह आरोप साबित हो गया था कि चुनाव में उन्होंने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है। एक अन्य तरह के जीप घोटाले के सिलसिले में 3 अक्तूबर 1977 को सीबीआइ ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर अगले दिन दिल्ली के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट ने सबूत मांगा तो सीबीआइ के वकील ने कहा कि जांच हो रही है। मजिस्ट्रेट ने श्रीमती गांधी को रिहा करने का आदेश दे दिया। 1979 में जनता पाटह्न में आंतरिक कलह के कारण मोरारजी देसाई सरकार गिर गई। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को संदेश भेजा कि आप संजय गांधी के खिलाफ जारी मुकदमे को वापस ले लें। चरण सिंह ने इन्कार किया तो उनकी सरकार गिरा दी गई। 1980 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी सत्ता में लौटीं। फिर कौन मुकदमा और कैसी जांच, सब कुछ समाप्त हो गया। जब 1990 में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी ने उन्हें संदेश भेजा कि बोफोर्स केस वापस कर लीजिए। ऐसा करने से मना करते हुए चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। बीते दिनों यह खबर आई कि बोफोर्स मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ज्ञात हो कि 2004 में बोफोर्स मामले में राजीव गांधी और संबंधित दलाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी। हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए सीबीआइ को अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि एजेंसी के ला अफसर ने अपील के लिए इसे एक मजबूत मामला बताया था। नेहरू-गांधी परिवार की समस्या यह है कि सरकार तथा संवैधानिक संस्थानों पर ओछे आरोपों और टिप्पणियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस परिवार को कानून से ऊपर नहीं मान रहे हैं। इसी कारण यह परिवार उन पर अनावश्यक रूप से हमलावर रहता है।

अधिकारियों को बेहतर परिणाम के लिए होना होगा दक्ष

अल्मोड़ा/रुद्रपुर। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत विकासभवन सभागार में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जनपद के विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा जनपद में सुशासन के मूल बहुत सिद्धांतों के तहत कार्य करने पर चर्चा की गई।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को सुशासन के सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए लोगों के लिए काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर परिणाम के लिए अधिकारियों को दक्ष होना होगा। उन्होंने कहा कि सभी को स्वयं से यह सवाल जरूर करना चाहिए कि जिस पद पर वें बैठे हैं क्या वह उस पद के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी उस पद पर बैठे व्यक्ति को उसके कार्य एवं अधिकारों के बारे में सही जानकारी नहीं होगी, तब तक वह उस पद की गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को अपने कार्य एवं अपने लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए लोगों को लाभान्वित करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सुशासन के सभी 8 सिद्धांत यथा - जवाबदेही, पारदर्शिता, भागीदारी, कानून का शासन, सहमति उन्मुख, समानता व समावेशिता, प्रभावशीलता व दक्षता तथा प्रतिक्रियाशीलता का पालन करना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इन सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए कोई भी अधिकारी अपनी दक्षता में वृद्धि) ला सकता है।इस दौरान अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए तथा बेस्ट प्रेक्टिशेज पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में मुख्य चिकित्साधिकारी डश्व आरसी पंत, जिला विकास अधिकारी एसके पंत, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. योगेश अग्रवाल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी रेनू भंडारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रुद्रपुर। सुशासन सप्ताह के अन्तर्गत प्रशासन गांव की ओर पर एक दिवसीय कार्यशाला जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में डा. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित हुई। कार्यशाला में सलाहकार राजस्व परिषद उदयराज सिंह ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला का सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सुशासन सप्ताह के अन्तर्गत प्रशासन गांव की ओर भारत सरकार व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने एवं समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओ का लाभ पहुंचाने हेतु सभी अधिकारी समन्वय बनाते हुए संजीदगी से कार्य करें। उन्होंने ग्रामीण उन्मुख योजनाओ पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने के साथ ही जनपद को अग्रणी जनपदो में लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी प्रशासन गांव के तहत गांव में जाकर रात्रि चौपाल लगाकर प्रवास करते हुए जनता से संवाद कर उनकी समस्याए सुने व उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए समस्याओ को निस्तारित करें। उन्होने कहा कि सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, सड़क, सामाजिक सुविधाए आदि देना सरकार की प्राथमिकता है इसलिए योजनाओ का प्रचार-प्रसार करते हुए जनता व जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाते हुए उन्हें जागरूक कर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। सलाहकार राजस्व परिषद सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर उन्मूख होकर प्रशासनिक अधिकारी गांवों में जाकर जनता के द्वार पर ही उनकी समस्याए सुनते हुए उनका निराकरण करें व योजनाओं का लाभ पहुंचाए। उन्होने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाए उनके गांव में जाकर उपलब्ध कराने के साथ ही भारत सरकार व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओ का लाभ जनता को पहुंचाया जाये तभी सरकार का मंतव्य व योजनाओ की सार्थकता होगी। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में बीस सूत्रीय कार्यक्रमो में जनपद गतवर्ष से लगातार प्रथम स्थान बनाये हुए है। आकांक्षी जनपद योजना के तहत बेहतर कार्य किये गये है व सारा योजना के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य किये जा रहे है। आधारभूत संरचना विकास में रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में वेलोड्रोम, बहुद्देशीय हॉल, सर्किट हाउस, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण/शहरी, रिंग रोड, मिनी स्पोर्टस स्टेडियम एवं छात्रावास, शहर में सड़क चौड़ीकरण/विस्तारीकरण, आंगनबाड़ी भवन, प्राधिकरण द्वारा किफायती आवास निर्माण, पीएमश्री विद्यालयो जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे है। कार्यशाला में मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, नगर आयुक्त, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मत्स्य अधिकारी सहित अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यो व प्रस्तावित कार्यो की विस्तृत जानकारिया दी व समस्याओं एवं सुझाव पर भी विस्तृत चर्चा की। कार्यशाला में उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. मनोज शर्मा, नगर आयुक्त नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, कौस्तुभ मिश्र, मुख्य कृषि अधिकारी डा. अभय सक्सेना, मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आशुतोष जोशी, जीएम उद्योग विपिन कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफील जमील, अधिशासी अभियंता लोनिवि ओपी सिंह, जल निगम सुनील जोशी, लघु सिंचाई सुशील कुमार, विद्युत उमाकांत चतुर्वेदी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध, जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन, एआरटीओ निखिल शर्मा, चक्रपाणी मिश्रा आदि मौजूद थे।

कूड़ा बीनने वाले बच्चों के मामले में दो को होगी सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कूड़ा बीनने वालों व उनके बच्चों को सरकार के द्वारा जारी सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी. नरेंद्र व वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि कूड़ा बीनने वालों व उनके बच्चों के कल्याण के लिए एक प्लान बनाकर 2 जनवरी तक एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी की तिथि नियत की है।

हाईकोर्ट के आदेश पर आज निदेशक शहरी विकास वीडियो कश्वन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुई। उनके द्वारा कहा गया कि एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 549 कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। उनमें से कई के पास राशन कार्ड,आधार कार्ड वोटर आईडी हैं और वे कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इनके उत्थान के लिए एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करें। सालसा व अन्य जिला विधिक प्राधिकरणों की रिपोर्ट के अनुसार कूड़ा बीनने वालो को जरूरी सामान व उनके बच्चों को राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जिसकी वजह से उनके बच्चे विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं।

सम्पादक : विनोद चन्द्र पनेरू
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक विनोद चन्द्र पनेरू द्वारा भीड़ापानी-ओखलकांडा प्रिन्टिंग प्रेस(मोती सिंह), भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी(नैनीताल) से मुद्रित तथा हरिपुर लालमणि पो.ऑ- देवलचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखंड) से प्रकाशित। मो. 9410354318 Email:-vinodpaneru123@gmail.com

हमेशा याद किया जाएगा चारों साहिबजादों का बलिदान

हल्द्वानी। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा सिंह संत बाबा जगत सिंह जी सीतापुर गौलापार में प्रतिभाग किया। वीर बाल दिवस के अवसर पर दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अमर बलिदान को नमन करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस इन्हीं महानायकों को स्मरण करने का अवसर है। जिन्होंने भारत की संस्कृति, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कहा कि गुरु गोविंद सिंह साहब के चारों साहिबजादों का बलिदान न केवल भारतीय इतिहास बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। वीर साहिबजादों के अद्वितीय त्याग और बलिदान को चिर-स्मरणीय बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। कहा कि इस पवित्र अवसर पर उपस्थित सभी माता-पिता और शिक्षकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को हमारे नायकों के बारे में बताएं और उनकी वीर गाथाओं को सुनाएँ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर गर्व का अनुभव करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिख फेडरेशन हल्द्वानी द्वारा गुरु तेग बहादुर स्कूल में मेरी सिखी मेरी शान प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुए 10 बच्चों को पुरस्कार वितरित किया। बता दें वीर साहिबजादों बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ने मात्र 17 वर्ष और 15 वर्ष की आयु में चमकौर के युद्ध में अद्वितीय शौर्य और साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने केवल 9 और 6 वर्ष की आयु में सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा दी गई अमानवीय यातनाओं का सामना किया, परंतु धर्म की रक्षा के अपने प्रण पर अडिग रहे।26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था से समझौता करने के बजाय अपने प्राणों की आहुति दे दी।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुरुद्वारा प्रबंधक राजेंद्र सिंह, संरक्षक बलजीत सिंह, राजेंद्र सिंह,गुरु वेद सिंह खजांची, जगतार सिंह सेक्रेटरी, इंद्रजीत सिंह, गुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, जगविंदर सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट गोलापार भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल आदि मौजूद थे।

बाल श्रम पर लगाएं प्रभावी अंकुश

बागेश्वर। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बीती गुरुवार को श्रम विभाग की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिले में बालश्रम कतई न हो इस दिशा में व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं खनन क्षेत्रों में नियमित छापेमारी अभियान चलाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सरकार की श्रमिक हितैषी योजनाओं का लाभ भी समय से श्रमिकों को प्रदान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इस काम में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की सख्त हिदायत दी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में काम कर रहें श्रमिकों का पंजीकरण अवश्य करा लें। साथ ही प्रवासी श्रमिक के लिए भी कार्य करने की जरूरत है। कार्य स्थल पर श्रमिकों के रहने,खाने-पीने तथा नहाने व शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था कार्यदायी संस्था से सुनिश्चित करायी जाए। यदि श्रमिकों के साथ उनके बच्चें आएं है तो उनके पढ़ाने के लिए भी कार्य करने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिकों के हितों के साथ खिलवाड़ कतई क्षम्य नही होगा। उन्होंने कहा कि छापेमारी अभियान में यदि जानकारी के अभाव या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे बालश्रम करते हुए पाए जाते है तो उनकी काउंसलिंग अवश्य करा ली जाए तथा सम्बंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। डीएम ने छापेमारी अभियानों की पाक्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दिए। बैठक में सीडीओ आरसी तिवारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी पीआर शैल, सदस्य कुलदीप मटियानी, लक्ष्मी सत्तू, एएस दानू आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र के सम्मान में फुल कोर्ट रिफ्रेंस

कहा, अधिवक्ताओं व हाईकोर्ट स्टाफ की समस्याओं का आपसी समन्वय से समाधान कराएंगे

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायरधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र के सम्मान में बीती शुक्रवार को हाईकोर्ट में फुल कोर्ट रिफ्रेंस का आयोजन हुआ । इस मौके पर मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य न्यायधीश नियुक्त होने की उन्हें खुशी है । कहा कि न्याय हित में बार व बेंच मिलकर काम करेंगे और वे अपने अधिकार के मुताबिक अधिवक्ताओं व हाईकोर्ट स्टाफ की समस्याओं का आपसी समन्वय से समाधान कराएंगे। न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के 14 वें मुख्य न्यायाधीश हैं । न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र का स्वागत करते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत का धनी राज्य है । प्रसिद्ध चार धाम यहां की पहचान है और हिमालय यहां की धरोहर है । उन्होंने देवभूमि में न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड हाईकोर्ट न्यायिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। स्वागत कार्यक्रम को महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी एस मेहता ने भी सम्बोधित किया । समारोह का संचालन रजिस्ट्रार जनरल कहकशां खान ने किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी, न्यायमूर्ति आलोक वर्मा, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल,न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, शासकीय अधिवक्ता अमित भट्ट, बार कौंसिल के अध्यक्ष डश्. महेंद्र पाल सिंह, बार एसोसिएशन के महासचिव वीरेंद्र रावत, भुवनेश जोशी, पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह रावत, एम सी कांडपाल, डी के शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायधीश जे सी एस रावत, न्यायमूर्ति टण्डन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पन्त, सालसा के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी,जिला जज नैनीताल सुबीर कुमार,कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी कुमाऊँ डा. योगेंद्र रावत, जिलाधिकारी नैनीताल वन्दना सिंह, एस एस पी नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद थे।

आचार संहिता के नियमों का पढ़ाया पाठ

बागेश्वर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सीडीओ आरसी तिवारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित तमाम जानकारियां दी गई।

बीती शुक्रवार को विकास भवन सभागार में बैठक के दौरान सीडीओ ने सभी राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने जाने के लिए सहयोग की अपील की। साथ ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता लागू होने के बाद प्रत्याशियों के नामांकन, घोषणा पत्र और आचार संहिता के दौरान आयोग की गाइडलाइन और दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों की रैलियों, रोड शो और अन्य होने वाले चुनावी आयोजनों के लिए खर्च के प्रावधान की भी जानकारी दी गई। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि जिले व शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपना सहयोग दें। चुनाव प्रचार सामग्री में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बैठक में नोडल अधिकारी व्यय/वरिष्ठ कोषाधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 8 लाख एवं सदस्य के लिए 80 हजार व्यय सीमा निर्धारित की गई है। जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष हेतु 3 लाख एवं सदस्य के लिए 50 हजार व्यय सीमा निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्याशी को नामांकन से लेकर परिणाम आने तक का खर्चा का ब्यौरा प्रत्येक दिन निर्धारित प्रारूप में व्यय टीम को देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों को रैली, विज्ञापन प्रचार-प्रसार के साथ ही वर्तमान में चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को नागर निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान राजनैतिक प्रकृति से सम्बन्धित विज्ञापन टेलीविजन, रेडियो चैनल, श्रव्य, दृश्य प्रदर्शनों, इंटरनेट आधारित मीडिया, केबिल नेटवर्क सहित वेवसाइट पर प्रकाशन से पूर्व सम्बंधित आरओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बैठक में पीडी शिल्पी पंत, डीडीओ संगीता आर्या, वरिष्ठ कोषाधिकारी जितेंद्र उपाध्याय, खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता, जिला महामंत्री भाजपा संजय परिहार, प्रतिनिधि भाजपा मदन राम आगरी, प्रदेश सचिव कांग्रेस कुंदन गिरी आदि उपस्थित रहे।

स्पोर्ट्स सिटी के रूप में उभर रहे प्रदेश के कई शहर

मुख्यमंत्री और खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38 वे राष्ट्रीय खेलों की मशाल को दिखाई हरी झंडी

हल्द्वानी। 38 वे राष्ट्रीय खेलों की ऊर्जा और उमंग से देवभूमि को प्रकाशित करने के लिए खेल मशाल ष्तेजस्विनीष गुरुवार को हल्द्वानी के गौलापार स्टेडियम से 3823 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हुई। तेजस्विनी (मशाल) और प्रचार रथ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गौलापार के बैडमिंटन काम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों से इन खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि 38वे खेल की मेजबानी राज्य को मिले है। हम सबका प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय खेल को भव्य और बेहतर तरीके से आयोजित कर मिसाल पेश की जाए। साथ ही संकल्प से शिखर तक की यह यात्रा आम जन के सहयोग से राज्य को शिखर तक ले जाएगी। सीएम ने कहा कि 13 जिलों के 99 स्थानों पर यह मशाल घूमेगी और आम जन को यात्रा के जोड़कर जागरूक करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने हेतु प्रतिब)ता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा खिलाड़ियों को कोच मुहैया करवाना हो, खेल का माहौल प्रदान करना हो, या फिर उन्हें आर्थिक सहायता देनी हो, हमारी सरकार प्रत्येक स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के हमारे खिलाड़ियों को 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रतिमाह प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ ही 10 हजार रुपए प्रति खिलाड़ी खेल उपकरण खरीदने हेतु भी दिए जा रहे हैं। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 17 हजार से अधिक खिलाड़ियों को कुल 33 करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा जहां एक ओर प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कश्वलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को पुनः लागू करने एवं प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना करने जैसे अनेकों निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कश्वन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों के मानदेय में भी 78 प्रतिशत से 140 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है साथ ही हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन कर उसमें 16 करोड. रूपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान भी किया है। धामी ने कहा कि खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही हमारी सरकार प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निरंतर सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ ही पहले से बने स्टेडियम और स्विमिंग पूलों का भी पुनर्निर्माण किया गया है। धामी ने कहा वाटर स्पोर्ट्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही शूटिंग रेंज को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून जैसे प्रदेश के कई शहर स्पोर्ट्स सिटी के रूप में उभर रहे हैं इसके साथ ही उत्तरकाशी और चंपावत जैसे क्षेत्रों में भी छोटे-छोटे खेल स्टेडियमों का निर्माण किया है। धामी ने कहा कि शीघ्र ही कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहा हैं। जिससे न केवल हल्द्वानी क्षेत्र के खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा बल्कि पूरे प्रदेश के खिलाड़ी भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में होने जा रहें 38 वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन न केवल हमारे खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का एक सुनहरा मौका है, बल्कि इस आयोजन के माध्यम से पूरे प्रदेश में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज से प्रारंभ होने वाली राष्ट्रीय खेलों की ये मशाल यात्रा आगामी राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अधिक से अधिक मेडल लाकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने हेतु प्रेरित करेगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज से राष्ट्रीय खेलों के औपचारिक आयोजन शुरू हो रहे हैं और खिलाड़ियों को जीत के अपने संकल्प को इतना मजबूत करना होगा कि वह शिखर तक पहुंच सकें। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप इन खेलों में इतिहास बदल दीजिए, हमें टोप 5 में आना है। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कर सके तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बन जाएंगे, आपकी देखादेखी प्रदेश में हजारों खिलाड़ियों की फौज तैयार होगी। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने खेल को कैरियर बनाने के लिए युवाओं के खातिर सारे रास्ते खोल दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाएं न सिर्फ खिलाड़ियों को तैयार करने में बचपन से उनकी मदद कर रही है बल्कि पदक जीतने पर अब उनका करियर बनाने की गारंटी भी सरकार की है। अगले 33 दिन खेल मशाल तेजस्विनी 3823 किलोमीटर का सफर करते हुए प्रदेश के सभी 13 जिलों से होकर गुजरेगी और खेल उद्घाटन की पूर्व संध्या पर देहरादून पहुंचेगी। इस अवसर पर लालकुआँ विधायक मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व मंत्री और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत, भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य आदि मौजूद रहे।

खिलाड़ियों का तीर्थ बनेगा गौलापार

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि गौलापार को खेल विश्वविद्यालय के रूप में बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है,और अब गौलापार खिलाड़ियों का नया तीर्थ बनकर उभरेगा। खेल विश्वविद्यालय में सिर्फ खिलाड़ियों का हुनर तराशने में मदद करेगा बल्कि उनके करियर को भी संवारेगा। कार्यक्रम मे बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, डा. मोहन सिंह बिष्ट, रामसिंह कैडा, अध्यक्ष खेल महासंघ महेश नेगी, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, डा अनिल कपूर डब्बू, दिनेश आर्य,मजहर नईम नवाब, मनोज साह, विकास भगत, रंजन बर्गली, सचिन साह, योगेश रजवार, प्रकाश हरबोला, चतुर सिंह बोरा के साथ ही प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी डा. योगेन्द्र रावत, जिलाधिकारी वंदना, सीडीओ अशोक कुमार पाण्डे, एसएसपी पीएन मीणा, निदेशक खेल प्रशान्त आर्य, उपनिदेशक खेल राशिका सिद्विकी, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह, जिला क्रीडा अधिकारी निर्मला पंत, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रतीक जोशी के साथ ही खिलाडी, खेलप्रेमी, गणमान्य, मातृशक्ति आदि लोग मौजूद थे।

हादसे रोकने को पर्वतीय रूटों पर चलाएं सघन चेकिंग अभियान : धामी

एसटीएच पहुंचे सीएम ने जाना भीमताल हादसे के घायलों का हाल

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीती गुरुवार को एक दिवसीय कार्यक्रम में हल्द्वानी पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने डा सुशीला तिवारी अस्पताल में भीमताल में एक दिन पूर्व हुए बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए।

साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सड़क हादसों को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बृहस्पतिवार को अपने प्रस्तावित कार्यक्रम में हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने बुधवार को भीमताल में बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की।

उन्होंने घायलों के परिजनों से भी मुलाकात की साथ ही उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों को आवश्यकता अनुसार हायर सेंटर रेफर करने के भी निर्देश दिए। बता दें बस हादसे में 5 लोगों की मौत और गंभीर रुप से दो घायलों को एम्स ;षिकेश हेली एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया गया।जबकि अन्य घायलों का इलाज एसटीएच में किया जा रहा है। कहा कि बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा पांच लाख जबकि सड़क सुरक्षा निधि से दो लाख और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से तीन लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तीन लाख एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को 15 से 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे सड़क हादसों को रोकने के लिए अन्य राज्यों से आ रही गाड़ियों के लाइसेंस की जांच और अन्य दस्तावेज की जांच संघन चेंकिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही यातायात को नियंत्रण करने के लिए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को जिम्मेदारी दी गई।जो सभी संबंधित विभागों से समन्वय कर नियंत्रित करेंगे।

डीएम ने किया बागेश्वर थाने का निरीक्षण

बागेश्वर। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बागेश्वर थाने का औचक निरीक्षण किया। विभिन्न व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन किया व थाने में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेने के निर्देश थानाध्यक्ष को दिए। डीएम ने बीती शुक्रवार को बागेश्वर थाने को निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने स्थानीय अभिसूचना इकाई के कार्यालय का निरीक्षण किया। जीर्ण शीर्ण पुराने भवनों के साथ ही आवासीय भवनों के मरम्मतीकरण के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उसके बाद जिलाधिकारी ने थाने का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने महिला हैल्प लाइन व महिला हैल्प डैस्क का निरीक्षण करते हुए तैनात कार्मिकों से विभिन्न जानकारियां ली। कहा कि महिला हैल्प लाइन में आने वाली फरियादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए। तथा समय समय पर सम्बंधितों की काउंसलिंग करायी जाय। उन्होंने सत्यापन के कार्यो को भी पूर्ण पारदर्शिता से साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। तथा फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जाय। यदि कोई फरियादी प्राथमिकी दर्ज कराने आता है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाय तथा समय पर विवेचना करके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने बाल मित्र कक्ष का निरीक्षण किया तथा खोया-पाया व गुमशुदा संबंधी जानकारी ली आपदा उपकरणों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उपकरणों को हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखा जाय। इस दौरान थानाध्यक्ष कैलाश नेगी,एलआईयू इंस्पेक्टर विजय कुमार मठवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।